



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84]  
No. 84]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2006/ज्येष्ठ 1, 1928  
NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2006/JYAISTHA 1, 1928

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

### अधिसूचना

मुंबई, 19 मई, 2006

सं. टीएएमपी/20/2005/एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा गोदियों में प्रभारित कंटेनर प्रहस्तन प्रभारों से संबंधित, दरमान में संशोधन तथा संबद्ध दरमान की वैधता के विस्तार हेतु, मुंबई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्तावों का, संलग्न आदेशानुसार, निपटान करता है।

### अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/20/2005-एमबीपीटी

मुंबई पत्तन न्यास

आवेदक

### आदेश

(मई 2006 के 11 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने, दिनांक 13 सितंबर 2005 को गोदियों के भीतर कंटेनरों के प्रहस्तन हेतु सम्मिश्र कंटेनर दर के निर्धारण के लिए मुंबई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित एक आदेश पारित किया था। प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सम्मिश्र कंटेनर दर 31 मार्च 2006 तक वैध थी।

2.1. पोत पर पोत हमाली, पोत से तट पर अन्तरण, बर्थ और कंटेनर यार्ड के बीच में आवागमन, यार्ड पर कंटेनरों को उठाने तथा उतारने और कुछ समायोजन सहित कंटेनरों के पोतघाट भाड़ा घटक के लिए (तत्कालीन) प्रचलित मदवार प्रभारों को, उक्त विविध प्रकार के प्रचालन के लिए (तत्कालीन) प्रचलित दरमान में निर्धारित अलग-अलग प्रशुल्क के बदले सबको समूहबद्ध करके सम्मिश्र कंटेनर दर का निर्धारण किया गया था।

2.2. (तत्कालीन) प्रचलित पोत पर पोत हमाली उगाही में जो अब सम्मिश्र कंटेनर दर के घटकों में से एक बनी हुई है, कंटेनरों का बांधना तथा खोलना भी सम्मिलित था। चूंकि पोत पर कंटेनरों को बांधना और खोलना एक जलयान एजेंट की जिम्मेदारी है, इसलिए जलयान एजेंट द्वारा कंटेनरों को बांधने और खोलने के काम के लिए एक छूट प्रदान करने हेतु एमबीपीटी के दरमान में एक प्रावधान किया गया था।

2.3. संदर्भित प्रकरण की परामर्श प्रक्रिया के दौरान एमबीपीटी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था कि क्या (प्रस्तावित) सम्मिश्र कन्टेनर दर में, कन्टेनरों को बांधने तथा खोलने की सेवाएँ प्रदान करना शामिल है। एमबीपीटी को यह भी सलाह दी गयी थी कि यदि पत्तन द्वारा बांधने और खोलने की सेवाएँ प्रदान नहीं की जाती हैं तो उसके लिए छूट को प्रस्तावित किया जाये। इसके प्रत्युत्तर में एमबीपीटी ने यह सूचित किया कि सम्मिश्र कन्टेनर दर में कन्टेनरों को बांधने और खोलने की सेवाएँ शामिल नहीं हैं। तथापि, यदि एमबीपीटी द्वारा कन्टेनरों को बांधने और खोलने की सेवाएँ प्रदान नहीं की जाती हैं तो भी पत्तन ने उसके लिए छूट प्रदान करने की व्यवस्था को जारी रखने का प्रस्ताव किया है। तदनुसार कन्टेनरों को बांधने तथा खोलने की सेवाएँ प्रदान न किये जाने पर गोदी दरमान की धारा 4(ग) के तहत प्रचलित छूट-रु. 30/- प्रत्येक कन्टेनर जारी रखने के प्रावधान को एमबीपीटी गोदियों पर प्रभारित दरमान के खण्ड V के तहत उप-खण्ड (क) और (ख) के टिप्पण (V) के रूप में सम्मिलित किया गया था। दिनांक 13 सितंबर 2005 के आदेश के पैरा (xxvii) में इस स्थिति की व्याख्या की गयी थी।

3. अब एमबीपीटी ने अपने पत्र सं.एफए/एसीसी/227/1437 दिनांक 18 फरवरी 2006 द्वारा यह सूचित किया है कि कन्टेनरों की सम्मिश्र कन्टेनर दर में, कन्टेनरों को बांधने और खोलने के लिए प्रदान की गई सेवाएँ सम्मिलित हैं और उसने इस प्राधिकरण से दिनांक 13 सितंबर 2005 को पारित आदेश के पैरा 11(xxviii) में से उद्भूत विसंगत स्थिति को ठीक करने हेतु अनुरोध किया है।

4. कथित विसंगति एमबीपीटी द्वारा प्रासंगिक कार्यवाही में गलत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के कारण उभरी है, यह स्थिति विसंगत इसलिए है क्योंकि किसी भी तत्व के लिए छूट कैसी दी जा सकती है जबकि वह तत्व सम्मिश्र दर में शामिल ही नहीं है। किन्तु उसी समय, यह गतिविधि चलाने वाले उपयोगकर्ता न्यायोचित रूप से राहत के हकदार है क्योंकि इससे पहले मदवार दर में पोतों को बांधने और खोलने का तत्व शामिल था। एमबीपीटी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधित स्पष्टीकरण के मद्देनजर इस प्राधिकरण के निर्णय तथा एमबीपीटी की स्थिति को सही रूप से प्रतिबिम्बित करने हेतु दिनांक 13 सितंबर 2005 के आदेश के पैरा 11 (xxviii) को संशोधित करना आवश्यक है। दिनांक 13 सितंबर 2005 को पारित आदेश का पैरा 11 (xxviii) और उसका आवश्यक संशोधन निम्नप्रकार से सारणीबद्ध है।

पैरा सं. 11(xxviii)	पैरा सं. 11(xxviii) का संशोधन
वर्तमान, पोत पर पोत हमाली प्रभार में कन्टेनरों को खोलना/बांधना सम्मिलित होता है। इस संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में एमबीपीटी ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित कन्टेनर दर में कन्टेनरों को बांधने/खोलने के लिए दी जानेवाली सेवाएँ समाहित नहीं हैं और इसने प्रस्ताव किया है कि गोदी दरमान के खंड 4(ग) के अन्तर्गत वर्तमान छूट जारी रखा जाय। तदनुसार कन्टेनरों को बांधने/खोलने के लिए सेवाएँ प्रदान न करने पर गोदी दरमान के खंड 4 (ग) के अधीन वर्तमान छूट के लिए दरमान में प्रावधान सम्मिलित किया गया है।	वर्तमान, पोत पर पोत हमाली प्रभार में कन्टेनरों को खोलना/बांधना सम्मिलित होता है। इस संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में एमबीपीटी ने अपने पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण को संशोधित कर दिया और सूचित किया कि कन्टेनर दर में कन्टेनरों को बांधने/खोलने के लिए दी जानेवाली सेवाएँ समाहित हैं; और इसने प्रस्ताव किया है कि गोदी दरमान के खंड 4(ग) के अन्तर्गत वर्तमान छूट जारी रखा जाय। तदनुसार कन्टेनरों को बांधने/खोलने के लिए सेवाएँ प्रदान न करने पर गोदी दरमान के खंड 4 (ग) के अधीन वर्तमान छूट के लिए दरमान में प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

5. दिनांक 13 सितंबर 2005 को पारित आदेश में संभावित संशोधन के मद्देनजर दरमान के खण्ड V के उपखण्ड (क) और (ख) की संबंधित टिप्पण सं. (iii) में निम्नलिखित पूर्वव्यापी संशोधन की आवश्यकता है :-

प्रचलित	संशोधित
उपरोक्त प्रभारों में पोत पर पोत हमाली प्रभार, पोतघाट पर प्रहस्तन प्रीस्टेक क्षेत्र में निर्यात कन्टेनरों को चढ़ाना/आयात कन्टेनरों को उतारना, कन्टेनरों को पोतघाट तथा प्रीस्टेक क्षेत्र/आरसीडी यार्ड के बीच में से हटाना, आईसीडी कन्टेनरों को रेलवे वेगनों से उतारना/पर चढ़ाना सम्मिलित है।	उपरोक्त प्रभारों में कन्टेनरों को बांधने/खोलने को समाहित करते हुए पोत पर पोत-हमाली प्रभार, पोतघाट पर प्रहस्तन प्रीस्टेक क्षेत्र पर निर्यात कन्टेनरों को चढ़ाना/आयात कन्टेनरों को उतारना, कन्टेनरों को पोतघाट तथा प्रीस्टेक क्षेत्र/आरसीडी यार्ड के बीच में से हटाना, आईसीडी कन्टेनरों को रेलवे वेगनों से उतारना/पर चढ़ाना सम्मिलित है।

6.1. एमबीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 7 अप्रैल 2006 द्वारा अन्य बातों के साथ इस प्राधिकरण से यह भी अनुरोध किया है कि व्यापक प्रशुल्क प्रस्ताव अनुपेक्षित होने तक प्रचलित सम्मिश्र कन्टेनर दर को 31 मार्च 2006 से आगे भी जारी रखने की अनुमति दी जाये।

6.2. सम्मिश्र कन्टेनर दर के निर्धारण हेतु अपना प्रस्ताव दाखिल करते समय एमबीपीटी ने, केवल एक वर्ष अर्थात् 2005-06 के लिए बहिर्बेशन सहित लागत विवरण प्रस्तुत की थी। चूंकि लागत विश्लेषण एक ही वर्ष पर आधारित था, इस प्राधिकरण ने सम्मिश्र कन्टेनर दर की वैधता को 31 मार्च 2006 तक निर्धारित किया।

6.3. एमबीपीटी ने गोदी दरमान के खण्ड IV पर, गोदियों के भीतर कन्टेनरों के प्रहस्तन हेतु सम्मिश्र कन्टेनर दर के प्रस्ताव को अपने सामान्य संशोधन प्रस्ताव में सम्मिलित किया है। यह उल्लेखनीय है कि पत्तन ने प्रचलित दरों को बिना परिवर्तन के, जारी रखने का प्रस्ताव किया है।

7. एमबीपीटी द्वारा दाखिल सामान्य संशोधन प्रस्ताव को परामर्श हेतु ले लिया गया है। अंतिम विचार हेतु परिपक्व होने के लिए प्रस्ताव को और कुछ अधिक समय लगेगा। एमबीपीटी की गोदियों के भीतर कन्टेनरों के प्रहस्तन हेतु, प्रचलित सम्मिश्र कन्टेनर दर की वैधता को 31 मार्च 2006 से आगे छः माह के लिए अथवा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होनेवाले एमबीपीटी के दरमान के संशोधन हेतु प्राप्त व्यापक प्रस्ताव के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि, इनमें से जो भी पहले हो तबतक, विस्तार करने के लिए यह प्राधिकरण सन्नद्ध है।

8. फलस्वरूप और उपर्युक्त कारणों से तथा समग्र विचारविमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण निम्नलिखित अनुमोदित करता है :

(i) प्रकरण सं. टीएमपी/20/2005-एमबीपीटी में दिनांक 13 सितंबर 2005 को पारित आदेश पैरा सं. 11(xxviii) निम्नप्रकार से संशोधित किया जाता है :

“वर्तमान, पोत पर पोत हमाली प्रभार में कन्टेनरों को खोलना/बांधना सम्मिलित है। इस संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में एमबीपीटी ने अपने पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण को संशोधित कर दिया है और सूचित किया है कि कन्टेनर दर में कन्टेनरों को बांधने/खोलने के लिए दी जानेवाली सेवाएँ समाहित हैं, और इसने प्रस्ताव किया है कि गोदी दरमान के खंड 4(ग) के अन्तर्गत वर्तमान छूट जारी रखी जाय। तदनुसार कन्टेनरों को बांधने/खोलने के लिए सेवाएँ प्रदान न करने पर गोदी दरमान के खंड 4(ग) के अधीन वर्तमान छूट के लिए दरमान में एक प्रावधान सम्मिलित किया गया है।”

(ii) दिनांक 13 सितंबर 2005 को पारित पूर्ववर्ती आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि से, गोदियों पर प्रभारित दरमान के खण्ड V के उपखण्ड (क) और (ख) के टिप्पण सं. (iii) को, निम्नप्रकार से पूर्ववर्ती प्रभाव से संशोधित किया जाता है :

“उपरोक्त प्रभारों में कन्टेनरों का बांधना/खोलना सहित, पोत पर पोत-हमाली प्रभार, पोतघाट पर प्रहस्तन, प्रीस्टेक क्षेत्र से निर्यात कन्टेनरों को चढ़ाना/आयात कन्टेनरों को उतारना, कन्टेनरों को पोतघाट तथा प्रीस्टेक क्षेत्र/आरसीडी यार्ड के बीच में से हटाना, आईसीडी कन्टेनरों को रेलवे वेगनों से उतारना/पर चढ़ाना सम्मिलित है।”

(iii) प्रकरण सं. टीएमपी/20/2005-एमबीपीटी में दिनांक 13 सितंबर 2005 के आदेश के माध्यम से, मुंबई पत्तन न्यास के दरमान में संशोधन की वैधता 31 मार्च 2006 से आगे, 6 माह की अवधि के लिए या मुंबई पत्तन न्यास द्वारा अपने दरमान के सामान्य संशोधन हेतु प्रस्ताव पर पारित होनेवाले आदेश की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो विस्तारित की जाती है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[ विज्ञापन-III/IV/143/2005/असा. ]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 19th May, 2006

**No. TAMP/20/2005-MBPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposals of the Mumbai Port Trust for amendment to the Scale of Rates charged at the docks relating to container handling charges and extension of the validity of the relevant Scale of Rates as in the Order appended hereto.

### SCHEDULE

**Case No. TAMP/20/2005 - MBPT**

The Mumbai Port Trust

Applicant

### ORDER

(Passed on this 11<sup>th</sup> day of May 2006)

This Authority passed an Order dated 13 September 2005 relating to a proposal from the Mumbai Port Trust (MBPT) for fixation of composite box rate for handling of containers within the docks. The composite box rates approved by this Authority were valid till 31 March 2006.

2.1. The composite box rate was fixed by grouping of the (then) existing itemized charges for on-board stevedoring, ship to shore transfer, movement between berth and container yard, lift on / lift off at yard and also wharfage component of containers with some adjustments as against separate tariff prescribed in the (then) existing Scale of Rates for the said various operations.

2.2. The (then) existing on-board stevedoring levy, now forming one of the components of composite box rate, included lashing / unlashings of containers. Since lashing / unlashings of containers on-board the vessel is the responsibility of the vessel agent, a provision was made in the Scale of Rates of MBPT for granting rebate for lashing / unlashings work done by the vessel agent.

2.3. In the course of consultation process of the case in reference, the MBPT was requested to clarify whether the (proposed) composite box rate covered providing services towards lashing / unlashings of containers. The MBPT was also advised to propose rebate if the lashing / unlashings services are not provided by the port. In response, the MBPT stated that the composite box rate did not cover the services rendered for lashing / unlashings of containers. However, the port proposed to continue with the arrangement of granting rebate if the lashing / unlashings services are not provided by the MBPT. Accordingly, a provision for continuance of the existing rebate of Rs.30 per container under Section 4(c) of the Dock Scale of Rates for the services not rendered for lashing / unlashings of containers was included as Note (v) to Sub-section (A) and (B) under Section V of the Scale of Rates charged at Docks of the MBPT. This position was explained in paragraph 11 (xxviii) of Order dated 13 September 2005.

3. Now, the MBPT vide its letter No.FA/ACC/227/1437 dated 18 February 2006 has stated that composite box rate for containers covers services rendered for lashing / unlashings of containers and requested this Authority to rectify the anomalous position arising out of paragraph 11 (xxviii) of the Order dated 13 September 2005.

4. The reported anomalous position has arisen due to a wrong clarification furnished by the MBPT in the relevant proceedings. The position is anomalous because no rebate can be granted for an element not included in the composite rate but at the same time the users who carry out this activity are justifiably entitled to relief in rate since the erstwhile-itemised rate included an element for lashing/ unlashings. In view of the revised clarification furnished by MBPT, the paragraph 11 (xxviii) of Order dated 13 September 2005 needs to be revised, to correctly reflect the position obtaining at the MBPT and decision of this Authority. The paragraph 11 (xxviii) of Order dated 13 September 2005 and the revision needed are tabulated below:

Paragraph No. 11 (xxviii)	Amendment to paragraph 11 (xxviii)
The existing onboard stevedoring levy includes lashing / unlashings of containers. To a query in this regard, the MBPT has clarified that the proposed box rate does not cover the services rendered for lashing / unlashings of containers; and, it has proposed that the existing rebate under Section 4(C) of Dock Scale of Rates may continue. Accordingly, a provision for existing rebate under Section 4(C) of Dock Scale of Rates for the services not rendered for lashing/unlashings of containers is included in the Scale of Rates.	The existing on-board stevedoring levy includes lashing / unlashings of containers. To a query in this regard, the MBPT has revised its earlier clarification and stated that the box rate covers services rendered for lashing / unlashings of containers; and, it has proposed that the existing rebate under Section IV (C) of Dock Scale of Rates may be continue. Accordingly, a provision for existing rebate under section IV (C) of Dock Scale of Rates for the services not rendered for lashing / unlashings of containers is included in the Scale of Rates.

5. In view of the revision (to be) effected in the Order dated 13 September 2005, the relevant note no. (iii) to sub-section (A) and (B) in Section V of the Scale of Rates needs retrospective correction as follows:

Existing	Corrected
The above charges include on board stevedoring charges, handling at shipside, lift on of export/ lift off of import containers at the pre-stake area, removal of container between shipside and pre-stake/ RCD yard, loading/ off loading of ICD containers on Railway Wagons	The above charges include on board stevedoring charges including lashing/ unlashings, handling at shipside, lift on of export/ lift off of import containers at the pre-stake area, removal of container between shipside and pre-stake/ RCD yard, loading/ off loading of ICD containers on Railway Wagons

6.1. The MBPT vide its letter dated 7 April 2006, *inter alia*, has requested this Authority to allow it to continue with the existing composite box rates beyond 31 March 2006 till the comprehensive tariff proposal is approved.

6.2. At the time of filing of its proposal for fixation of the composite box rates, the MBPT furnished the cost statement with projection for one year only i.e. 2005-06. Since the cost analysis was based on one year, this Authority fixed the validity of the composite box rates till 31 March 2006.

6.3. The MBPT has included the proposal for composite box rates for handling Containers within the Docks at Section IV of the Dock Scale of Rates in its general revision proposal. It is noteworthy that the port has proposed to continue with the existing rates without modification.

7. The general revision proposal filed by MBPT is taken on consultation. It will take some more time for the proposal to mature for final consideration. This Authority is inclined to extend the validity of the existing composite box rates for handling Containers within the Docks of MBPT for 6 months beyond 31 March 2006 or till the effective date of implementation of the comprehensive proposal for revision of Scale of Rates of MBPT (to be) approved by this Authority, whichever is earlier.

8. In the result, and for the reasons given above, and based on the collective application of mind, this Authority approves the following:

- (i). The paragraph no. 11(xxviii) of the Order dated 13 September 2005 in case no. TAMP/20/2005-MBPT is revised as follows:

“The existing on-board stevedoring levy includes lashing / unlashings of containers. To a query in this regard, the MBPT has revised its earlier clarification and stated that the box rate covers services rendered for lashing / unlashings of containers; and, it has proposed that the existing rebate under Section IV (C) of Dock Scale of Rates may continue. Accordingly, a provision for existing rebate under section IV (C) of Dock Scale of Rates for the services not rendered for lashing / unlashings of containers is included in the Scale of Rates.”

- (ii). Note no. (iii) to Sub-section (A) and (B) of Section V to the Scale of Rates charged at Docks is amended as follows with retrospective effect from the effective date of implementation of the earlier Order dated 13 September 2005:

“The above charges include on board stevedoring charges including lashing/ unlashings, handling at shipside, lift on of export/ lift off of import containers at the pre-stake area, removal of container between shipside and pre-stake/ RCD yard, loading/ off loading of ICD containers on Railway Wagons.”

- (iii). The validity of the amendments to the Scale of Rates of Mumbai Port Trust effected vide Order dated 13 September 2005 in Case no. TAMP/20/2005-MBPT is extended for a period of 6 months beyond 31 March 2006 or till the effective date of implementation of the Order to be passed on the proposal of the Mumbai Port Trust for general revision of its Scale of Rates, whichever is earlier.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT III/IV/143/2005/Exty.]

1539 GT/2006-2